# वैश्वीकरणः आर्थिक प्रभाव
## (भारतीय परिदृश्य में)

■ **डॉ0 हृषिकेश नारायण सिंह**
प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग,
कमला देवी बाजोरिया महाविद्यालय,
दुबहड़, बलिया

वैश्वीकरण का इतिहास लगभग दो दशक पुराना है। जिस वर्ष 1991 सोवियत संघ का विघटन हुआ उसी वर्ष भारत में आर्थिक सुधारों का श्रीगणेश हुआ। राजकीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीयकरण और सरकारी नियंत्रण के प्रति भारत का मोह भंग हो गया। फलतः विनियमन विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। व्यापार को निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उन सभी प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया जो इस मार्ग के वर्षों से बाधक बने हुए थे। भारत की आर्थिक निति में होने वाले इस क्रांतिकारी परिवर्तनों के प्रति कुछ लोगों ने अनेक प्रकार की आशंकाएँ प्रकट की. भारत की आर्थिक सम्प्रभुता समाप्त हो जायेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चुंगल में फॅस जायेगी। लेकिन विश्व की गति, दिशा और व्यापक स्थिति को देखते हुए विरोधी लोग ढीले पड़ गये और उन्होंने धीरे–धीरे वैश्वीकरण की निति से समझौता कर लिया। सौभाग्य से विरोधियों की आशंकाएँ निर्मूल सिद्ध हुई। आज सम्पूर्ण विश्व एक ही धारा में वैश्वीकरण की धारा में प्रवाहित हो रहा है।

यह स्वाभाविक प्रश्न है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले विकासशील देशों को क्या लाभ हुआ है। वैश्वीकरण के पूर्व और उसके पश्चात की स्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। इस सन्दर्भ में यह देखना होगा कि घरेलू उत्पाद, बुनियादी क्षेत्र, मुद्रा स्फिति, निर्यात, स्वदेशी व्यापार, स्वदेशी एवं विदेशी पूँजी निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी मुद्रा भण्डार, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा चिकित्सा एवं सामाजिक क्षेत्र की अन्य सेवाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। विकासशील देशों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन से सम्बन्धित तालिकाएं बताती हैं कि सकल घरेलू उत्पाद, निवेश, राजकोषीय घाटा, मुद्रा स्फिति, निर्यात, विदेशी ऋण, निरक्षरता, शिशु एवं मृत्युदर क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए हैं, वे निश्चय ही उत्साहवर्द्धक हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि वैश्वीकरण की निति के अभाव में क्या यह परिवर्तन नहीं होते? उत्तर है– होते, परन्तु इतने कम समय में एक साथ इतने परिवर्तन नहीं होते, हॉ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वैश्वीकरण जनित आर्थिक सुधारों का प्रभाव गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय नहीं दिखाई दिया है। जनसंख्या की वृद्धि के फलस्वरूप विश्व के समस्त देशों में चीन को छोड़कर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।

कुछ देशों में विशेष कारणोंवश वैश्वीकरण का अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा है।

भारत का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत सन् 1980–90 के दशक में थी, वहीं 1993–2001 के दौरान 7 प्रतिशत रही। पिछले चार वर्षों में यह दर 7.5 प्रतिशत 2003–04, 8.5 प्रतिशत, (2004–05), 9 प्रतिशत 2005–06 में और 2006–07 में यह बढ़कर 9.2 प्रतिशत रही। प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह का विश्वास है कि यह रफ्तार 10 प्रतिशत को पार कर जायेगी।

भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 2000–01 में 39 अरब डालर था जो 2003–04 बढ़कर 107 अरब डालर हो गया। 2005–06 में 145 अरब डालर और फरवरी 2007 में 180 अरब डालर और वर्तमान में यह 200 अरब डालर का ऑकड़ा पार कर चुका है। भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सितम्बर 1991 से सितम्बर 2006 के बीच 1,81,566 करोड़ (43.29 अरब डालर) रहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रमुख रूप से बिजली उपकरण, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, सेवा क्षेत्र, दूरसंचार के क्षेत्र में रहा।

वर्तमान में भारत विश्व के सम्पूर्ण आउट सोर्सिंग बाजार के 45 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण रखे हुए है।

पूँजी बाजार के क्षेत्र में भारतीय कम्पनियॉ शेयरों के मूल्यों के हिसाब से चौथे स्थान पर है। पहला स्थान अमेरिका (17000 अरब डालर), दूसरा जापान (4800 अरब डालर), तीसरा चीन (1000 अरब डालर) का है।

फोबर्स सूची 2007 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 40 रही, जो जापान के 24, चीन के 17 फ्रांस के 14 और इटली के 14 से अधिक थी।

एक प्रेस विज्ञप्ति में सन् 2007 को भारत को अमीर वर्ष कहा गया। भारत की सभी अरबपतियों की सम्पूर्ण पूँजी का मूल्य 2007 में 7.5 लाख करोड़ था, जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के 91 कम्पनियों के कुल मूल्य का 3.93 लाख करोड़ से अधिक था। कृषि आज भी भारतीया अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। कृषि का न केवल भोजन तथा पोषण लोगों को प्रदान करने में महत्व है बल्कि औद्योगिक क्षेत्र तथा नियति के लिए कच्चे माल के रूप में भी योगदान करता है।

सन् 1951 में कृषि 72 प्रतिशत लोगों को रोजगार तथा सकल घरेलू उत्पाद में 59 प्रतिशत का योगदान था। वहीं सन् 2001 में 58 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर रही, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान गिरकर 24 प्रतिशत पर पहुॅच गयी, वहीं 2006–07 में यह 22 प्रतिशत तक पहुॅच गयी। यह सब किसानों के प्रति व्यक्ति आय में कमी तथा उनपर बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण हुआ।

भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की संख्या जो 1987 में 35 प्रतिशत थी बढ़कर 1997 में 45 प्रतिशत तक पहुॅच गयी। वह आगे बढ़ते हुए सन् 2005 में 55 प्रतिशत के स्तर तक पहुॅच चुकी है। किसान या तो भूख या आत्महत्या से मर रहे हैं। कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्य सभा में 18 मई 2006 को बताया कि 1993–2003 के बीच करीब 1 लाख किसानों ने आत्म हत्या की जिसका प्रमुख कारण कर्ज को न चुका पाना रहा है।

भारत में खेती पर निर्भर परिवारों की संख्या 60 प्रतिशत है, वहीं ब्रिटेन में 2 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमरीका में 2 प्रतिशत तथा जापान में यह मात्र 3 प्रतिशत है। विकसित देशों में खेती पर निर्भर लोगों की संख्या अत्यन्त कम है। अतः उदारीकरण उनके लिए लाभप्रद है क्योंकि वैश्वीकरण निर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के लिए ही लाभप्रद है।

यूरोप में सरकार की तरफ से प्रतिदिन प्रति आय 2डालर का अनुदान दिया जाता है जबकि विकासशील देशों की आधी से अधिक जनसंख्या इससे काफी कम धन में गुजर बसर करती हैं। अर्थात विकसित देशों की आय का स्तर विकासशील देशों की गरीब जनता के स्तर से काफी ऊॅचा है।